

मानवाधिकार और पर्यावरण

प्रलिस के लिये:

[अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय \(ICC\)](#), [मानवाधिकार](#), स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण का अधिकार (R2hE), [वित्तीय कार्रवाई कार्य बल \(FATF\)](#), भारतीय संविधान का [अनुच्छेद 21](#) ।

मेन्स के लिये:

मानव अधिकार और पर्यावरण, मानव अधिकार के रूप में पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र की भूमिकाएँ ।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्वविद्यालयों के एक समूह ने एक संयुक्त नोट लिखकर [अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय \(ICC\)](#) से [मानवाधिकारों](#) से जुड़े पर्यावरणीय क्षरण से निपटने के लिये कदम उठाने का आग्रह किया है ।

- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार, सामान्यतः गंभीर पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने वाली मानवीय गतिविधियाँ मानव अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं, जो **कानि रसंहार जैसे मानवता के विरुद्ध अपराध के समान होती हैं** ।
- यह परिरेक्ष्य **स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण (R2hE) के अधिकार** को महत्त्वपूर्ण मानते हुए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है ।

मानवाधिकार और पर्यावरण का संबंध:

- मानवाधिकार:**
 - [संयुक्त राष्ट्र \(UN\)](#) के अनुसार, मानवाधिकार नस्ल, लैंगिक, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य स्थितिकी परवाह किये बिना सभी मनुष्यों के अंतरनिहित अधिकार हैं ।
 - मानवाधिकार अंतरनिहित अधिकार होते हैं, जो हमारे पास हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में मौजूद हैं, वे हमें किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किये जाते हैं ।
 - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर, 1948 को पेरिस में [मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा \(UDHR\)](#) को सभी देशों और लोगों के लिये उपलब्ध के एक सामान्य मानक के रूप में अपनाया ।
 - इसमें जीवन व [स्वतंत्रता](#) का अधिकार, अधीनता और यातना से स्वतंत्रता, [राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता](#), कार्य करने व शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि शामिल हैं ।
 - बिना किसी [भेदभाव](#) के प्रत्येक जीव इन अधिकारों का हकदार है ।
- मानवाधिकार के रूप में पर्यावरण की आवश्यकता:**
 - सामान्य तौर पर मानवाधिकार की अवधारणा [द्वितीय विश्व युद्ध](#) के बाद उभरी, लेकिन उन मानवाधिकारों में से एक के रूप में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार कभी भी प्राथमिकता नहीं थी ।
 - स्वस्थ पर्यावरण [जीवन के अधिकार](#) का एक अनिवार्य पहलू है, न केवल मनुष्यों के लिये बल्कि ग्रह पर **अन्य जानवरों के लिये भी** ।
 - स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन **संभवतः जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन है** ।
 - जब पर्यावरणीय अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ग्रह और ग्रह के लोगों के समक्ष स्वास्थ्य एवं खुशहाली में कमी जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं ।
 - पर्यावरणीय क्षरण अंततः वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डाल सकता है ।
- स्वच्छ, स्वस्थ और सतत् पर्यावरण (R2hE) के अधिकार को मान्यता प्रदान करना:**
 - R2hE** एक मौलिक मानव अधिकार है, जिसमें सभी व्यक्तियों को ऐसे वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है जो उनके स्वास्थ्य एवं हितों के अनुकूल है और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।
 - यह अधिकार मानव कल्याण और पर्यावरण को बनाए रखने के बीच अंतरसंबंध को मान्यता प्रदान करता है ।

- स्वस्थ पर्यावरण से संबंधित चुनौतियाँ और चतियाँ:
 - कानूनी बाधाएँ: अपराधियों को जवाबदेह ठहराना, चाहे वे राजनेता हों, कॉर्पोरेट संस्थाएँ, या आपराधिक सडिकेट या ऐसे व्यक्तियों जो गंभीर कानूनी बाधाएँ उत्पन्न करते हों।
 - **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)** की एक रिपोर्ट में बेहतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और दृढ़ राष्ट्रीय वधिक आवश्यकता पर ध्यान देते हुए इन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।
 - **ह्यूमन राइट्स वॉच**, 2020 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे पर्यावरणीय वनिश हाशिये पर रहने वाले समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिनके पास लड़ने की सीमिति क्षमता होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य, आजीविका और स्वच्छ जल तक पहुँच प्रभावित होती है।
 - पर्यावरणीय अपराधों की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति: पर्यावरणीय प्रणालियों की परस्पर जुड़ी प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों में वैश्विक व्यापार एवं सीमा पार प्रदूषकों की आवाजाही के कारण पर्यावरणीय अपराधों के लिये एक अंतरराष्ट्रीय आयाम को प्रदर्शित करती है।
 - **पर्यावरणीय अपराध से मनी लॉन्ड्रिंग**: पर्यावरणीय अपराध से मनी लॉन्ड्रिंग पर **वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), 2021** की रिपोर्ट में पाया गया कि अपराधी संसाधन आपूर्ति शृंखलाओं में कानूनी एवं अवैध वस्तुओं के साथ-साथ शीघ्रता से भुगतानों को प्राप्त करने वाली कंपनियों का उपयोग करके अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
 - **अवैध वित्तीय प्रवाह**: संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरणीय अपराधों के माध्यम से अर्जति धन का एक गंतव्य बन गया है (वर्ष 2023 में वित्तीय जवाबदेही एवं कॉर्पोरेट पारदर्शिता गठबंधन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार) जो अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने तथा जलवायु संकट से निपटने के वैश्विक उपायों को कमजोर करता है।
- भारत में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार:
 - भारत में जीवन के अधिकार का विधि प्रकार से उपयोग किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने का अधिकार, जीवन की गुणवत्ता, सम्मान के साथ जीने का अधिकार तथा आजीविका का अधिकार शामिल हैं। भारत में इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
 - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** में कहा गया है: 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।'।
 - **सर्वोच्च न्यायालय** ने इस नकारात्मक अधिकार का दो प्रकार से विस्तार किया।
 - सर्वप्रथम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिये।
 - दूसरा, न्यायालय ने **अनुच्छेद 21** द्वारा नहित कई अव्यक्त स्वतंत्रताओं को मान्यता दी।
 - इसी दूसरी पद्धति से सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करते हुए स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को इसमें शामिल किया।

भारत में पर्यावरण संरक्षण कानून क्या हैं?

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972**
- **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974**
- **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981**
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986**
- **राष्ट्रीय हरति अधिनियम, 2010**

स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या हैं?

- **28 जुलाई, 2022** को **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें घोषणा की गई कि ग्रह पर हर किसी को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है।
 - यह प्रस्ताव राज्यों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं व्यावसायिक उद्यमों से सभी के लिये स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान करता है।
- **मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** जैसे प्रयास: पर्यावरण के मैगनाकार्टा के रूप में जाना जाता है, ने प्रतिनिधिपारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों, वायु, पानी, भूमि, वनस्पतियों और जीवों को सुरक्षित रखने की अनिवार्यता पर ज़ोर दिया।
 - इसने वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु सावधानीपूर्वक योजना या प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- **वर्ष 1987** में पर्यावरण तथा विकास पर **वर्ल्ड आयोग की रिपोर्ट** ने पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास के उद्देश्य से 22 कानूनी सिद्धांत सामने रखे।
 - इस रिपोर्ट ने **सतत् विकास की अवधारणा प्रस्तुत** की साथ ही पर्यावरण, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों के अंतरसंबंध पर ज़ोर भी दिया गया।
- **'केयरिंग फॉर द अर्थ, वर्ष 1991'** तथा वर्ष 1992 के **'अर्थ समिति'** ने दोहराया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सद्भाव में स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जीने का अधिकार है।

स्वस्थ पर्यावरण से संबंधित मामले क्या हैं?

- **एम.सी.मेहता बनाम यू.ओ.आई., 1986:**
 - पर्यावरण संबंधी नरिक्षरता को दूर करने के लिये दिये गए नरिदेश:
 - सनिमा हॉल या वीडियो पार्लरों को भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण पर तैयार की गई कम से कम दो सलाइड परदर्शति करनी होंगी ।
 - दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर्यावरण पर रोचक कार्यक्रमों के लिये परतदिनि 5-7 मनिट का समय नरिधारति करते हैं ।
 - स्कूलों और कॉलेजों में करमबद्ध तरीके से पर्यावरण को एक अनविर्य वषिय बनाया जाए तथा वशिवदियालय इसके लिये एक पाठ्यकरम नरिधारति करेंगे ।
- **एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ, 1996:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के लिये आवश्यक बुनयिदी पर्यावरणीय तत्त्वों अरथात् हवा, पानी और मृदा में की गई कोई भी गड़बड़ी जीवन के लिये हानिकारक होगी और इसे परदूषति नहीं कथिया जा सकता है ।
- **ग्रामीण मुकदमेबाज़ी और हकदारी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1985:**
 - चूना पत्थर खनन, जसिने मसूरी की पहाड़ियों को पेड़ों और जंगलों से ढक दिया तथा मृदा के कटाव में बढ़ोतरी की, जसिके परणामस्वरूप भूमगित जल चैनल अवरुद्ध हो गए, पर परतबिंध लगा दिया गया ।
- **तरूण भारत संघ (एन.जी.ओ.) बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया, 1993:**
 - सरसिका बाघ अभयारण्य के आसपास की सभी 400 संगमरमर की खदानों को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि इससे उस क्षेत्र के वन्यजीवों को खतरा है ।
- **गंगा और यमुना के परदूषण की रोकथाम, 1995:**
 - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कानपुर में गंगा, कलकत्ता में हुगली और दलिली में यमुना के कनारे बसे सभी परदूषणकारी उद्योगों को हटाने के लिये कहा ।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय (International Criminal Court- ICC) के कानूनी ढाँचे में R2hE को शामिल करना, एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में बनकर उभरा है ।
- **रोम संवधि** के तहत पर्यावरणीय अपराधों को अभियोजन योग्य अपराधों के रूप में स्वीकार करके ICC इन उल्लंघनों को व्यवस्थित रूप से संबोधति कर सकता है ।
- पर्यावरणीय अपराधों के अपराधियों पर मुकदमा चलाना अनविर्य है, लेकिन इन अपराधों को सुवधाजनक बनाने वाले अंतर्रनहिति संरचनात्मक मुद्दों को संबोधति करना भी उतना ही आवश्यक है ।
- नयामक खामियों को दूर करने और परवर्तन तंत्र को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना सर्वोपरि है ।
- भ्रष्टाचार से नपिटने, वत्तित्तीय लेनदेन में पारदर्शति बढ़ाने और मनी-लॉन्ड्रिंग वरिधी उपायों को मज़बूत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पहल अपरहिर्य हैं ।
- भारत ने पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से वभिनिन कानून बनाए हैं, इन कानूनों को परभावी ढंग से लागू करने और उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये उन्हें अद्यतन करने पर ध्यान केंद्रति कथिया जाना चाहयि ।

दृष्टिभेन्स अभ्यास परशन:

परशन : भारत में पर्यावरणीय कषरण और मानवाधिकारों पर इसके परभाव के संदर्भ में, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सुनश्चिति करने के लिये मौजूदा कानूनी ढाँचे और नीतियों का वशिलेषण कीजयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के परशन

??????:

परशन: मूल अधिकारों के अतरिकित्त भारत के संवधान का नमिनलखिति में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के सदिधांतों एवं प्रावधानों को परतबिबिति करता/करते है/हैं? (2020)

1. उद्देशिका
2. राज्य के नीतिनिदिशक तत्त्व
3. मूल कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का परयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। उनकी संरचनात्मक एवं व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/human-rights-and-environment>

